दिनांक 23.02.2022

वितरितः 11.04.2022

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

याचिका संख्या 319 (एम./एस.)

बाल सुग्रीव सिंह और अन्य ...। **याचिकाकर्ता**

बनाम

प्रेम सिंह और एक अन्य ...। **विपक्षी**

अधिवक्ताः याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंह।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखने से पूर्व और विशेष रूप से विपक्षी संख्या–01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के प्रकाश में, इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सवालों का बेहतर उत्तर देने के लिए, क्षेत्र को नियंत्रित करने के रूप में सटीक कानून से समझने की आवश्यकता है। इस संदर्भ के दो समानांतर राजस्व कानून हैं, जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा मामले पर बहस करने के लिए अपने तर्क के समर्थन में लिए जा रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (इसके बाद इसे यूपीजेडए और एल.आर. अधिनियम के रूप में जाना जाता है) का प्रावधान है। वास्तव में उक्त अधिनियम के अतंर्गत पहलूओं को समझने के लिए, यू.पी.जेड.ए. और एल एंड आर अधिनियम के प्रावधान, एक विशेष संविधि हैं, जिसे अधिनियम और अधिनियम के तहत परिभाषित कृषि भूमि पर प्रबंधन, विनियमों और अधिकारों के हस्तांतरण को शासित करने वाले राज्य द्वारा तैयार किया गया है, यही कारण है कि यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम को भारत के संविधान के

अनुच्छेद 31–बी के तहत तैयार संविधान की दसवीं अनुसूची में रखा गया है और इसे सीरियल नंबर 11 पर अपनी प्रविष्टि मिलती है।

2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 31–ठ कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन को प्रावधानित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 31–। के तहत निहित प्रावधानों के अपवाद के रूप में राज्य कानूनों द्वारा तैयार किए गए हैं, इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 31–ठ के तहत शामिल कानून से जुड़ा एक खंड है, जो एक वैध कानून है और कोई भी अधिनियम और विनियम जो दसवीं अनुसूची या इनमें से किसी में निहित नहीं हैं। इसके प्रावधानों को शून्य माना जाएगा या आधार पर शून्य हो जाएगा, कि ऐसे अधिनियम या विनियम कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के साथ असंगत हैं या अधिनियम के विधानमंडल के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को कम करते हैं।

3. अर्थात् जहां तक यूपी जेडए और एल.आर. अधिनियम का संबंध है, इसे अधिनियम की धारा 3 उपधारा (14) के तहत परिभाषित भूमि के अधिकारों को विनियमित करने या उससे निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम होने का एक कानून दिया गया है, सिवाय उक्त अधिनियम के अध्याय VII की धारा 109 और 143 और 144 के तहत कवर की गई भूमि के अपवाद को छोड़कर। अधिनियम की धारा 229–बी के तहत घोषणा के अधिकार से संबंधित हैय यू.पी. जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत होल्डिंग का विभाजन, अधिनियम की धारा 209 के तहत कब्जे के लिए एक मुकदमा और ऐसी अन्य प्रमुख सिद्धांत कार्यवाही, जो पक्षकारों के अधिकार को निर्धारित करती है और लगभग यह पुरुष और महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित संपत्ति के अधिकारों से समन्वय स्थापित करने वाली नियमित कार्यवाही का आकार लेती है।

4. यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही अधिनियम की धारा 341 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जिसके आधार पर धारा 5 सहित कोर्ट फीस अधिनियम, परिसीमा अधिनियम के प्रावधानय साथ ही सिविल प्रक्रिया

संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम–5 के तहत प्रदान की गई कार्यवाहियों पर इसकी समग्रता में लागू किया गया है।

5. संविधि का दूसरा सेट जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि राज्य विधायिका ने उत्तर प्रदेश नामक एक अधिनियम तैयार किया था। भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 (जिसे बाद में भू–राजस्व अधिनियम कहा जाता है), जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालय के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा लगातार देखा गया है कि इसमें शासित कार्यवाही अध्याय III के उप–खंड–सी में निहित हैय जो मुख्य रूप से मानचित्रों और राजस्व रिकॉर्ड की निरंतरता से संबंधित है, वे प्रकृति में सारांश हैं। उक्त अधिनियम, जिसके साथ हम अधिक चिंतित होंगे, के तहत कब्जा के हस्तांतरण के उत्तराधिकार की रिपोर्ट का प्रावधान है, जिसके आधार पर दावा किए गए अधिकार का विघटन होता है और अध्याय III के तहत विचार की गई प्रक्रियाओं के संबंध में प्रक्रियाओं को उन प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित किया जाता है, जो उक्त अधिनियम के अध्याय X में निहित हैं। चूंकि अदालतें इस प्रकार बनाई गई हैं भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत या यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, राजस्व न्यायालय मैनुअल को कार्यवाही को विनियमित करने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए संकलित किया गया है, जो ऊपर उल्लिखित किसी भी अधिनियम के तहत विचार किया जाता है।

6. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री अमर सिंह, पुत्र श्री राम प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद का खाता नंबर 8–3 में 0.980 हेक्टेयर क्षेत्र में पड़ी जमीन के एक टुकड़े पर विशेष अधिकार है (इसके बाद इसे विवादित संपत्ति कहा जाता है)। यह अभिकथित है कि श्री अमर सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 27.06.1997 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी और यह 27.06.1997 की उक्त पंजीकृत वसीयत की ताकत के तहत है, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्वर्गीय श्री अमर सिंह की संपत्ति पर अधिकार उन्हें हस्तांतरित किया गया था।

7. दौरान विचरण यह निष्कर्ष निकला था कि याचिकाकर्ताओं ने भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नायब तहसीलदार की अदालत में धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसे 2007–2008 के केस नंबर 30/106 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उनका नाम 27.06.1997 के वसीयतकर्ता के स्थान पर उनके नामों को प्रतिस्थापित करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। इस प्रकार 2007–2008 के केस नंबर–30/106 के माध्यम से धारा 34 के तहत की गई कार्यवाही में, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क है कि प्रकाशन हुआ था जिसमें धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने से संबंधित आम जनता को जानकारी दी गई थी, जिससे आपत्तियां आमंत्रित की गईं और याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तरदाता नंबर–1, वास्तव में 2007–2008 के 106 के केस नंबर 30 की कार्यवाही में उपस्थित हुये हैं परन्तु उसने जानबूझकर कार्यवाही का विरोध करने में अपनी शिथिलता दिखाई थी और 20.01.2009 और 07.02.2009 को दो अवसरों पर उत्तरदाता नंबर–1 द्वारा स्थगन की मांग की गई थी जो अस्वीकार हुई और जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार चुनौती नहीं दिये जाने के कारण उसके हक में निस्तारित हुई।

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क है कि नायब तहसीलदार की अदालत ने 27.06.1997 की वसीयत के गवाहों की जांच करने के बाद, जिन्हें नायब तहसीलदार की विद्वान अदालत के समक्ष पेश किया गया था और लेखपाल से उक्त पर रिपोर्ट लेकर विवादित भूमि पर कब्जे के तथ्य का पता लगाने के पश्चात्, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर फैसला करने के लिए कार्यवाही अग्रेसित की गई तथा निर्णय दिनांकित् 1702.2009 के परिणाम स्वस्प 2706.1997 की वसीयत के आधार पर याचिकाकर्ताओं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं का यह भी तर्क है कि चूँकि विपक्षी संख्या–01 ने 29.08.2008 की अपनी उपस्थित दर्ज कराई हैं और वे कार्यवाही का विरोध कर रहे थे और विशेष रूप से जब उनका स्थगन आवेदन खारिज कर दिया गया था तथा याचिकाकर्ताओं के आवेदन दिनांकित् 17.02.2009 की अनुमति देने आदेश अधिनियम की धारा 34 अंतर्गत भू–राजस्व अधिनियम, विपक्षी की जानकारी में था और इस तरह की विलंबित अपील जिसे विपक्षीय संख्या–01 द्वारा 17.02. 2.2009 को दिये गये निर्णय के खिलाफ दायर किया गया था, मान्य नहीं होगा, विशेष रूप

से स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि 20.01.2009 और 07.02.2009 के स्थगन आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है।

9. यह भी संज्ञान में आया है कि विपक्षी संख्या–01 ने वास्तव में 17.02.2009 के फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये एक आवेदन दायर किया था तथा उक्त आवेदन पर एक प्रति दिनांकित् 17.03.2009 को प्राप्त भी की गई थी, लेकिन फिर भी भू–राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत समक्ष अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर नहीं की गई और दिनांक 18.04.2009 को दायर की गई, जो विलंब क्षमा आवेदन के साथ समर्थित कर संलग्न थी।

10. भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील की जाती है, भूमि राजस्व अधिनियम के तहत अपील करने की सीमा अवधि अधिनियम की धारा 214 के तहत निर्धारित की जाती है, जिसके तहत आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही पीड़ित व्यक्ति शिकायत दायर कर सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि चूँकि विपक्षी संख्या–01 द्वारा अपील केवल 18.04.2009 को भी दायर की गयी थी, इसलिये इसे समय सीमा से बाधित किया गया। जैसा कि पहले भी दर्शित है कि विपक्षीगण की अपील दिनांकित! 18.04.2009, विलंब माफी के आवेदन के साथ समर्थित किया गया है तथा उक्त विलंब आवेदन में इस आशय के क्षमा के कारण व्यक्त किये गये थे कि हालांकि विपक्षीगण द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिदिनांक 17.03.2009 को आवेदन कर प्राप्त किया गया था परन्तु प्रार्थी दिनांक 19.03. 2009 से 29.03.2009 के बीच बीमार था, इसलिये अपील दायर नहीं की जा सकी और जब उसने अपने अधिवक्ता को अपील तैयार करने के दिनांक 26.03.2009 को बुलाया तो अधिवक्ता की पत्नी बीमार हो गई और अपील तैयार नहीं हो सकी क्योंकि उसके अधिवक्ता की पत्नी का ईलाज 11.04.2009 से 12.04.2009 तक लगातार चला और इसके बाद फिर अपील दिनांक 18.04.2009 को विलंब माफी आवेदन के साथ दिनांक 18.04.2009 को अधिनियम की धारा 21 के तहत योजित की गई। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांकित् 16.12.2015 से विपक्षीगण की अपील स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार के आदेश दिनांकित् 17.02.2009 को अपास्त. किया गया तथा मामले का पुनः सुनवाई हेतु नायब तहसीलदार के न्यायालय में इस निदर्शे के साथ वापस प्रेषित किया

गयाकि मामले की पुनः सुनवाई कर, गुण–दोष के आधार पर दोनों पक्षों को सुनकर निस्तारण किया जाये। उक्त अपीलीय आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहॉ दिया गया हैः–

> **"अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 17.02.2009 खारिज किया जाता है। पत्रावली अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाये। आदेश की प्रति अवर न्यायालय की पत्रावली में रखी जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो।"**

11. यही वह अपीलीय आदेश है, जिस पर याचिकाकर्ता ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत निगरानी प्रस्तुत की है, और माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा अपने फैसले के पैरा–8 में की गई टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुये, जो प्रस्तुत निगरानी को निर्णय दिनांकित् 19.01.2022 से खारिज किया गया और 16.02.2015 के रिमांड के आदेश को पुष्ट किया गया है।

12. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने **2015 के पुनरीक्षण संख्या 85 बाल सुग्रीव सिंह और अन्य बनाम प्रेम सिंह और अन्य** के साथ–साथ 16.12.2015 के अपीलीय प्राधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए, वास्तव में, रिट याचिका के अपने संबोधन के दौरान, उस प्रश्न से मामले पर बहस की थी, जिसे रिट याचिका के पैरा–3 में तैयार किया गया है और संदर्भित किया गया है। जो यहाँ इस प्रकार हैः–

> ***"3. वर्तमान में शामिल विवादास्पद प्रश्न इस प्रकार हैंः–***
>
> **(क)** यह जानना कि क्या अपर कलेक्टर के पास उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील करने का कोई अधिकार क्षेत्र है और आदेश 41 नियम 23, 23 ए सीपीसी के अनुसार रिमांड की आवश्यकताओं के विरुद्ध विलंब क्षमादान आवेदन पर निर्णय लिए बिना, शीर्षक विवाद पर निर्णय लेने के लिए नामांतरण न्यायालय में मामला दर्ज करना।

(ख) क्या आदेश 41 सीपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील पर निर्णय लेते समय अतिरिक्त कलेक्टर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत बिना आवेदन के दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं?

13. वास्तव में, दौरान बहस याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो अपने तर्क के समर्थन में जोर दिया है, वह इस संदर्भ में है कि अपीलीय अदालत ने भूमि राजस्व अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 34 के तहत नए सिरे से आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को नायब तहसीलदार की अदालत में भेजकर कानून में गलती की है और चूँकि यह सारांश कार्यवाही थी इसलिये अपीलीय अदालत के पास रिमांड की कोई शक्ति नहीं है।

(i) अपीलीय अदालत द्वारा मामले को उसके नए निर्णय के लिए रिमांड पर भेजने की अधिकारिता के बारे में तर्क के पहले हिस्से का उत्तर, और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 216 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में दिया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैः–

अपीलीय न्यायालय की शक्तियांः –1) अपीलीय न्यायालय या तो अपील को स्वीकार कर सकता है या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर सकता है।

(2) यदि यह अपील को स्वीकार करता है, तो यह उसके खिलाफ अपील किए गए आदेश को उलट सकता है, बदल सकता है या पुष्टि कर सकता है या इस प्रकार की आगे की जांच करने या इस प्रकार के अतिरिक्त साक्ष्य को लेने के लिए निर्देशित कर सकता है, यदि आवश्यक हो तो यह स्वयं इस तरह के अतिरिक्त सबूत ले सकता है या वह इस तरह के निर्देशों के साथ मामले को निस्तारण के लिए भेज सकता है जैसा कि वह उचित समझता है। इस तरह धारा 216 की उपधारा (2) में अनिवार्य की शक्ति विशेष रूप से अपीलीय प्राधिकरण के पास निहित की गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास नीचे दी गई अदालत के समक्ष एक नए निर्णय के लिए रिमांड की अपनी शक्ति का अभाव था।

(ii) याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्क का दूसरा पहलू यह है कि प्रतिवादियों ने स्थगन के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने के 20.01.2009 और 07.02. 2009 के आदेशों पर सवाल नहीं उठाया था और याचिकाकर्ताओं की धारा 34 के तहत एक आवेदन की अनुमति देते हुये दिनांक 07.02.2009 को अपने गुण–दोष के आधार पर मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़े थे, यह नहीं माना जा सकता है कि स्थगन के उपरोक्त उम्मीदवारों को चुनौती दी गई थी।

(iii) इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार, न्यायालय द्वारा अपने गुण–दोष के आधार पर की गई कार्यवाही, लंबित आवेदनों को शामिल करते हुए, उन कार्यवाहियों में, उन्हें उनके गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेना होगा। न्यायालय को मुकदमे के तहत व्यक्ति के अतीत के आचरण को नहीं देखना चाहिए, ताकि कार्यवाही की वैधता का आकलन किया जा सके, जिसे विचार के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुपात 1997–98 **(न्यायमूर्ति डीके सेठ)** में रिपोर्ट किए गए फैसले में प्रदान किया गया है।

14. इस न्यायालय के मत में स्थगन आवेदन पर पारित आदेश, प्राधिकरण द्वारा पारित मुख्य आदेश को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, अर्थात् जो 17.02.2009 को पारित किया गया है, जिसमें उत्परिवर्तन आवेदन की अनुमति दी गई है और देरी क्षमा आवेदन के साथ धारा 210 के तहत अपील दायर करके इसे चुनौती देने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल इस कारण कि अपीलकर्ताओं को अपील की कार्यवाही का ज्ञान था, अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से स्थगन आवेदन खारिज होने के बाद इसे चुनौती नहीं दी है और यह अपने आप में प्रधान प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति के अधिकार को नहीं छीनेगा, अपील दायर करके इसे चुनौती देकर क्योंकि अपीलीय अधिकार से वंचित करने की कीमत पर स्थगन की अस्वीकृति के अंतवर्ती आवेदनों को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अतः याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि चूंकि स्थगन के दो आदेशों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए कोई अपील नहीं होगी, इस न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया है।

15. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ने इस मामले में यह भी तर्क दिया है कि नायब तहसीलदार द्वारा 17.02.2009 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और अपील को दिनांक 18.04.2009 को प्रस्तुत की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 214 के तहत प्रावधानिक समय सीमा 30 दिन भीतर के काफी लम्बे समय पश्चात् योजित हुई और इस तथ्य के बावजूद कि अपील के साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी है। अपीलीय न्यायालय ने अपने गुण–दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने से पहले देरी को माफ करते हुये आवेदन स्वीकार नहीं किया है।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलीय न्यायालय ने विलंब क्षमादान आवेदन पर निर्णय लिए बिना गुण–दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का प्रयास किया है, एक बार फिर इस न्यायालय द्वारा तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विलंब क्षमादान आवेदन के विरोध में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए बचाव को बहुत विस्तार से निपटाया किया गया है। 2008–2009 की अपील संख्या 52/36 में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपने निर्णय के पैरा–2 में और विलंब माफी आवेदन के निहितार्थों पर विचार करते हुए, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आंतरिक पृष्ठ 3 में **आरडी 2011, खंड 112, 61 प्रेम नाथ सिंह बनाम राज्य** में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में विलंब क्षमादान आवेदन पर विचार करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया है।

(क) और इसके परिणामस्वरूप अपील के गुण–दोष के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है और इसलिए एक टिप्पणी भी की गई है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क, जिसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था, कि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया को विशेष रूप से पैरा 197 और नियम 376 और 377 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में, राजस्व न्यायालय मैनुअल के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने इसके प्रभाव पर विचार किया था और दयानंदी बनाम रुक्मा डी स्वर्ण और अन्य के मामलों में 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुएय विशेष रूप से इसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है, पैरा 13 जिसमें अपील को स्वीकार कर लिया गया था और मामले को रिमांड पर भेज दिया गया था। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह

नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय अदालत ने 16.12.2015 का निर्णय पारित करने से पहले अपने गुण–दोष के आधार पर देरी के प्रभाव पर विचार नहीं किया है क्योंकि अदालत का इरादा काफी स्पष्ट था, और जिस तरह से धारा 5 के निहितार्थ पर विचार किया गया है, यह माना जाएगा कि अदालत द्वारा और देरी के पहलू पर विचार करने में विचार किया गया था और इसलिए अधिवक्ता द्वारा यह आधार लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देरी को माफ नहीं किया गया था और देरी को माफ किए बिना मामले पर फैसला किया गया था, मैं बल नहीं है, क्योंकि दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अपीलीय अदालत के झुकाव को दर्शाते हैं कि उसने आवेदन की संभावना से विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है और अपील पर फैसला करते समय देरी के पहलू पर विचार किया गया है।

17. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ने अपने पहले चरण की बहस में यह तर्क दिया था कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 और आदेश 41 नियम 23–ए के तहत निहित प्रावधान, जो रिमांड की शक्ति के साथ निहित हैं, भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बनाई गई अदालतों पर लागू नहीं होंगे।

18. दौरान बहस द्वारा इस न्यायालय ने बहस के दौरान, जब धारा 216 के तहत निहित प्रावधानों का उल्लेख किया था और विशेष रूप से, जब प्रक्रिया स्वयं भूमि सुधार अधिनियम के अध्याय द्वारा शासित होती है, तो इसके निहितार्थ सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 23 और आदेश 41 नियम 23–ए का धारा 210 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को धारा 216 के साथ पुनः व्यवस्थित करने और मामले को उसके नए निर्णय के लिए भेजने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि 16.12.2015 का अपीलीय निर्णय एक स्पष्ट दोष से ग्रस्त है क्योंकि सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन, जो उत्तरदाताओं द्वारा उनकी अपील के समर्थन में रखा गया था, गुण–दोष के आधार पर तय नहीं किया गया था और इसके समर्थन में दायर दस्तावेज को सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन की अनुमति दिए बिना विचार किया गया था।

20. इस महत्वपूर्ण मोड़ पर ही न्यायालय ने एक बार फिर से याचिकाकर्ताओं से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों

की प्रयोज्यता के अभाव में, कार्यवाही पर, जो प्रकृति में सारांशित हैं और भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के निहितार्थ कैसे दूर होंगे?

21. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों को बदलने के लिये यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के मद्देनजर, इसके नियम 176 में निहित प्रावधानों ने सीपीसी के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता प्रदान की है, जो राजस्व न्यायालयों द्वारा आयोजित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए निकाले गए हैं। विशेष रूप से, उन्होंने सीपीसी के आदेश 41 के तहत निहित प्रावधानों का भी उल्लेख किया है जिसमें सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत निहित प्रावधान शामिल हैं–

> ***राजस्व न्यायालय नियमावली के संगत नियम 176 को यहां दिया गया है:*** सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। आदेश XLI, आदेश XLII के नियम 2 से 4, 6 से 10, 15 से 29, 31 से 37 और डिक्री से अपील से संबंधित नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 99 और 144 के प्रावधान उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के तहत आदेशों से प्राप्त अपीलों पर लागू होंगे।

22. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के मद्देनजर, आदेश 41 के प्रावधान सीपीसी का नियम 27 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत सारांश कार्यवाही पर लागू होगा और विशेष रूप से, कार्यवाही की जांच करते समय, जो प्रकृति में सारांश है, इस न्यायालय का विचार है कि जब सारांश प्रक्रिया स्व–निहित संहिता के तहत आयोजित की जा रही है, जो इसके अध्याय 9 के तहत प्रदान किए गए अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को नियंत्रित करती है। इस घटना में, राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के तहत प्रावधान किए गए राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे, और इसके पीछे तर्क यह है कि यदि राजस्व न्यायालय मैनुअल के भाग–I को ध्यान में रखा जाता है, तो यह ''राजस्व न्यायालयों में मुकदमा, अपील और अन्य कार्यवाही'' से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया है। मामले में वर्तमान में शामिल सारांश कार्यवाही नहीं है, इसका अर्थ यह है कि सामान्य प्रक्रियात्मक नियम संविधि के तहत निहित विशिष्ट प्रक्रिया को ओवरराइड

नहीं करेगा, जिसमें कार्यवाही आयोजित की जा रही है। इसलिए, राजस्व न्यायालय मैनुअल में वैधानिक बल नहीं होगा, क्योंकि कानून का कोई स्रोत नहीं है, जिसके तहत, इसे अधिनियम के तहत परिकल्पित सारांश कार्यवाही की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की यह दलील इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है।

23. प्रथम दृष्टया अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया था, जो सभी राजस्व बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए थे। यह विधि द्वारा स्थापित है कि जिसके बारे में और विस्तार की आवश्यकता नहीं है, कि राजस्व बोर्ड के निर्णय, संवैधानिक न्यायालयों पर कानूनी और बाध्यकारी मिसाल नहीं हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अतः याचिकाकर्ताओं के मामले के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालयों में उनका कोई प्रेरक मूल्य नहीं हो सकता है। सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 23 के तहत या सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता और याचिकाकर्ताओं द्वारा आधारित अनुपात को स्वीकार न करने का औचित्य इस आधार पर है कि यदि लगभग सभी निर्णयों पर विचार किया जाता है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा आधारित प्राधिकारियों द्वारा निस्तारित किया गया है, तो वे सभी वह कार्यवाहियॉ थीं। जो विशेष संविधि के अंतर्गत नियमित रूप से आयोजित किए गए थे और जिनके पास अधिनियम की धारा 34 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत आयोजित सारांश कार्यवाही से निपटने के उद्देश्यों के लिए कोई संदर्भ नहीं है, जो केवल राजकोषीय प्रविष्टि है, जिसका लागू या विरोधी पक्ष के शीर्षक पर कोई प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिए गए न्याय निर्णयन इस प्रकार हैं: –

(i) 1971 में रिपोर्ट किए गए फैसले में ***आरडी 490 अजीत सिंह बनाम खम्भू सिंह और अन्य,*** यह एक ऐसा मामला था जो सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 के तहत अपीलीय अदालत की रिमांड की शक्तियों विचार कर रहा था, और सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 25, लेकिन ''यू.पी. जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत आयोजित कार्यवाही में, जो नियमित पक्ष पर थी,'' अर्थात एक

होल्डिंग का विभाजन जो एक नियमित प्रक्रिया है, जिस पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं, यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 341 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, यह सिद्धांत तत्काल मामले में लागू नहीं होगा, जो भूमि राजस्व अधिनियम, 1901-II के प्रावधानों के तहत किया जा रहा था।

(ii) दूसरा फैसला जिस पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया है, वह यह है कि जैसा कि ***आरडी 1972 (2) राम लाल बनाम भागगू*** में बताया गया है, जो फिर से यूपी किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम 1947 के पहलू और प्रावधानों और कार्यवाही को संचालित करने के निहितार्थ को विचार रहा था, जो उक्त प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे। यह निर्णय भी राजस्व बोर्ड द्वारा दिया गया एक निर्णय था, जिसका संवैधानिक न्यायालयों पर बाध्यकारी उदाहरण नहीं होगा और वह भी तब जब उक्त मामला, निर्णय के पैरा 4 में किए गए अवलोकनों के अनुसार, अधिनियम की धारा 209 के तहत आयोजित की जा रही कार्यवाही से संबंधित था, जिसे यूपी जेडए और एलआर अधिनियम की धारा 229–बी के साथ पढ़ा जाना था, जो भी यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित कार्यवाही हैं और इसका सारांश कार्यवाही पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं और वह भी विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि ये कार्यवाही नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित थीं।

(iii) याचिकाकर्ताओं के वकील ने ***1975 के आरडी 150 जमुना प्रसाद बनाम सत्य नारायण*** में रिपोर्ट किए गए एक और फैसले का हवाला दिया था, जिसके तहत आदेश 41 नियम 23 और 24 की प्रयोज्यता का बिन्दु उठाया गया था, जो सी.पी.एस. को कार्यवाही के लिए इसकी प्रयोज्यता में माना जा रहा था, जो यूपी जेडए और एल.आर. अधिनियम की धारा 229–बी के तहत आयोजित किया गया था। इसलिए, उक्त निर्णय भी एक बार फिर से राजस्व बोर्ड का होने के कारण और अधिकारों की घोषणा के साथ विशिष्ट विषय के साथ काम करने के कारण, वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होगा। वह भी तब जब यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.

अधिनियम के तहत कार्यवाही यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.अधिनियम की धारा 341 द्वारा शासित होती है, जिस पर सी.पी.सी. लागू होती है।

(iv) एक अन्य न्याय निर्णयन ***आरडी नरेश बनाम गांव सभा 1975*** आरडी पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बल दिया गया है, जहां लगभग एक समान सिद्धांत पर सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 के आवेदन से संबंधित विचार किया गया है, यानी अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमांड की शक्तियों को रिमांड की अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, वह भी एक ऐसा मामला था जिसे राजस्व बोर्ड द्वारा फिर से तय किया गया था।

(v) अंत में, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने ***1969 आरडी 115 अल्गू बनाम सीताला प्रसाद*** में रिपोर्ट किए गए न्याय निर्णयन का संदर्भ दिया था, जो सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 और 25 के प्रभाव से सम्बन्धित था, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए रिमांड के लिए आधार और क्या प्रारंभिक आधार पर मुकदमे का अंत और नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देना बिल्कुल आवश्यक था, यह एक बार फिर एक ऐसा मामला था जिस पर राजस्व बोर्ड द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा था, जहां वादी ने अधिनियम की धारा 209 के तहत मुकदमा दायर किया था, और भूमि का कब्जा हासिल करने का दावा कर रहा था, जिसे उन्होंने भूमिधर होने का दावा किया था। चूंकि यह निर्णय नियमित कार्यवाही से बाहर निकल रहा था और बोर्ड ऑफ खिन्न्यू द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए यह तत्काल मामले में लागू नहीं होगा जो विभिन्न अधिनियमों के तहत, सारांश मामलों से निपटता है। विशेष रूप से जब निर्णय देने वाली अदालतें अधीनस्थ अदालतें हैं, जिन पर उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

24. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि यदि किसी मामले में अपीलीय आदेश पर विचार किया जाता है, जब अपीलीय प्राधिकारी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, तो उसे गुण–दोष के आधार पर मामले से नहीं निस्तारित करना चाहिए था, जैसे कि वह साक्ष्यों

पर विचार करके और सराहना करके अपने गुण–दोष के आधार पर है, नियमित कार्यवाही कर रहा था, क्योंकि राजस्व न्यायालय मैनुअल के तहत, अध्याय 7 पैरा 176 के तहत निहित प्रावधानों के तहत, जिसका संदर्भ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया है, एक सारांश कार्यवाही में है जो धारा 34 के तहत आयोजित की जा रही है, जो भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील की उत्पत्ति थी। यह एक नियमित मुकदमे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है।

25. यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क की सराहना करने में असमर्थ है क्योंकि तथ्यात्मक रूप से, यह याचिकाकर्ता थे जो 27.06.1997 की पंजीकृत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा कर रहे थे, जैसा कि यह आरोप लगाया गया था, श्री अमर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था, और यह वही था जिसे 2007–2008 का ***केस नंबर 30/106*** मिला थाय भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत तहसीलदार की अदालत के समक्ष शुरू किया गया। यदि याचिकाकर्ता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि यह नियमित मामले का परीक्षण है, तो उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैय क्योंकि वे अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक ही समय में विरोधाभाषी होने की स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं। इसका कारण यह है कि यदि नायब तहसीलदार की अदालत द्वारा 17.02.2009 के सैद्धांतिक फैसले में दर्ज निष्कर्ष को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में यह याचिकाकर्ता ही थे जिन्होंने गवाह को प्रमाणित करके और हलका पटवारी की रिपोर्ट पर निर्भरता रखकर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, ताकि कब्जे के तथ्य को स्थापित किया जा सके और इसके बजाय यह वह था जो कार्यवाही में कदम रख रहा था। मानो वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत चल रही कार्यवाही की आड़ में अपने मालिकाना हक का फैसला करवा रहे हों। यदि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं वसीयत को साबित करने के लिए मामले के गुण–दोष पर साक्ष्य का लाभ उठाया है, तो उस स्थिति में धारा 34 के तहत आदेश प्राप्त करने के लिए, अपीलीय न्यायालय, जो विपक्षीगण द्वारा दायर की गई अपील है, जो कार्यवाही की निरंतरता है, इसके निहितार्थ और उन विचारों पर विचार करने के लिए बाध्य था क्योंकि इसके बीज थे जो नायब तहसीलदार के आदेश से अंकुरित हुए थे। दिनांक 17.02.2009 को ही यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय न्यायालय ने अपने

अधिकार क्षेत्र से बाहर का प्रयोग किया है क्योंकि अपीलीय न्यायालय निर्णय को पलटते समय तथ्यों और साक्ष्यों की सराहना करने के लिए बाध्य था।

26. इस तर्क को एक अन्य दृष्टिकोण से और अधिक सराहा जा सकता है कि भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधान, निष्कर्षों के बावजूद, जो भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए जाते हैं, धारा 219 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही तक कार्यवाही के किसी भी चरण में, जो कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है, जो अभी भी सक्षम राजस्व न्यायालयों द्वारा नियमित अधिकारों की घोषणा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और यही कारण है, विधायिका ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 40–ए के तहत निहित प्रावधानों का प्रावधान क्यों किया था, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों के बावजूद, वसीयत के आधार पर दावा किए गए अधिकार की घोषणा पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां यूपी जेडए और एल. आर. अधिनियम की धारा 169 के तहत दोष की अनुमति है और यदि धारा 40–ए की भावना को ध्यान में रखा जाता है, यहां तक कि साक्ष्य की सराहना के निष्कर्ष भी किसी भी प्रतिबंध को पैदा नहीं करेंगे या कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष के हित के लिए हानिकारक होंगे, उनके नियमित अधिकारों का फैसला करने में। इस तर्क को जारी रखते हुए याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने यह भी अभिकथित किया गया कि विपक्षीगण ने पहले ही निषेधाज्ञा की डिक्री लेने के लिए ***2005 का सिविल मुकदमा संख्या 02*** दायर किया था, जिसे 10.02.2012 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था और इसलिए वास्तव में विपक्षीगण के खिलाफ एक प्रतिबंध बनाता है।

27. मेरे आदेश पूरी मानवता के साथ, निषेधाज्ञा की कार्यवाही, चाहे अभिलेखों में शीर्षक या स्वामित्व या कब्जे का पता लगाना प्रकृति में एकमात्र आकस्मिक हो और इसका कोई असर नहीं होगा और वह भी विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जहां यहां तक कि सिविल मुकदमे का भी गुण–दोष के आधार पर फैसला नहीं किया गया था, इसे डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और इसलिए दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, अभियोजन के अभाव में मुकदमे को खारिज करने पर, एक पहलू हो सकता है, जिसे कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा जो

भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 40–ए के तहत निहित प्रावधानों द्वारा लागू किये हैं। अंत में, यदि लागू आदेशों के निहितार्थ को ध्यान में रखा जाता है और विशेष रूप सेः–

पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पैरा 8 में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में, रिमांड के अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने के लिए अपना तर्क निर्दिष्ट करने के लिएय वास्तव में रिमांड का आदेश एक वादकालीन आदेश का रूप लेता है, जहां कोई अधिकार अपनी योग्यता के आधार पर तय नहीं किए जाते हैं, बल्कि सभी मुद्दों को अभी भी समक्ष अदालत द्वारा पुनर्विचार के लिए खोला जाता है, जहां कार्यवाही को रिमांड पर भेज दिया गया है और इसलिए रिमांड का वार्ताकारी आदेश, चूंकि यह किसी भी अधिकार का अधिनिर्णयन नहीं है, एक वित्तीय अधिकार भी हो सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट 707 क्षितिज चंद्र बोस बनाम कांची के आयुक्त में रिपोर्ट किए गए निर्णयों*** में निर्धारित अनुपात को देखते हुए रिट याचिका पर रोक लगा दी जाएगी। निर्णय का पैरा 8 निम्नानुसार उल्लिखित हैः –

''उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि समय–समय पर किए गए कब्जे के छिटपुट कार्य प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों की प्रकृति के बारे में साक्ष्य का अध्ययन करने की भी परवाह नहीं की है और न ही यह पता लगाने के लिए कि क्या वे केवल छिटपुट या आकस्मिक थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि प्रतिकूल कब्जा निरंतरता और प्रचार में प्रभावी और पर्याप्त होना चाहिए था। यहां, उच्च न्यायालय ने कानून के एक बिंदु पर गलती की है। विधि के लिए केवल यह आवश्यक है कि कब्जा खुला होना चाहिए और बिना किसी प्रयास के होना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि कब्जा इतना प्रभावी होना चाहिए ताकि इसे मालिक के विशिष्ट ज्ञान में लाया जा सके। इस तरह की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है जहां खिताब से बाहर होने की गुंजाइश है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हालांकि, निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वादी का कब्जा नगरपालिका के पूर्ण ज्ञान के लिए शत्रुतापूर्ण था। इस संबंध में हम निचली अदालत और

अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त द्वारा शीर्षक और प्रतिकूल कब्जे के सवाल पर दर्ज किए गए सुविचारित निष्कर्षों से नीचे सहमत हो सकते हैं।

ट्रायल कोर्ट (पुनः शीर्षक): ''इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये रसीदें उपयुक्त भूमि से संबंधित हैं और इसलिए, वे वादी या उसके पिता द्वारा किराए का भुगतान दिखाती हैं। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि भूमि उन जमींदारों की थी जिनके भीतर यह जमींदारी थी। इसलिए, वादी के पिता ने उनसे समझौते द्वारा एक वैध शीर्षक प्राप्त किया।

पुनः प्रतिकूल कब्जाः ''इसलिए, मुझे लगता है कि वादी ने भी प्रतिकूल कब्जे से शीर्षक प्राप्त किया है क्योंकि वह और उसके पहले उसके पिता 1912 से 1957 तक इस भूमि के निरंतर कब्जे में थे, जब उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश से बेदखल कर दिया गया था।

अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त (पुनः शीर्षक) ''इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि एक्सट्स। 5 से 5(जी) उन्हीं भूमियों से संबंधित हैं जिनके लिए हुकुमनामा (उदात्त 18) को मंजूरी दी गई थी क्योंकि वे उसी क्षेत्र के लिए हैं जैसा कि हुकुमनामा में दिया गया है और इनमें से पहला नाम, एक्स्ट 5 निपटान के बाद पहले वर्ष के लिए है और 20.5.1913 को दिनांकित है। निश्चित रूप से हुकुमनामा (उदा. 18) द्वारा, जो अप्रकाशित दस्तावेज है, मुकदमे में भूमि का निपटान किया जा सकता है और यह निपटान के पक्ष में अच्छा शीर्षक पैदा कर सकता है क्योंकि निपटान कृषि उद्देश्य के लिए था और कब्जे की डिलीवरी और किराया रसीदों के अनुदान के साथ था। पी डब्ल्यू 1, 2, 6, 9 और 8 (वादी) ने और उसके पिता के निरंतर कब्जे के बारे में कहा है।

पुनः प्रतिकूल कब्जाः ''इस प्रकार ऊपर बताए गए तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वादी और उनके पिता 1912 से वर्ष 1954–55 तक मुकदमे में भूमि के कब्जे में आ रहे थे। नगरपालिका ने वादी और उसके पिता को 1924 से 1954–55 तक मुकदमा भूमि पर निर्माण सामग्री का भंडारण करने

से रोकने के लिए कई प्रयास किए। इस प्रकार वादी के पिता 1928–29 के नगरपालिका सर्वेक्षण से पहले और बाद में मुकदमा भूमि के कब्जे में साबित हुए। मौखिक साक्ष्य पी डब्ल्यू 1, 6, 5, 8 और 9 भी साबित करते हैं कि 1912 में जमींदार द्वारा निपटान के बाद वादी और उसके पिता का मुकदमा भूमि पर वास्तविक कब्जा था। इसलिए, नगरपालिका सर्वेक्षण प्रविष्टि की शुद्धता की धारणा को वादी द्वारा इस मामले में सफलतापूर्वक खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। ***2001 (92) आर.डी. राम भजन और अन्य बनाम उप निदेशक, इलाहाबाद और एक अन्य। निर्णय के पैरा 4 और 6*** को यहां दिया गया हैः ''4A एस.ओ.सी. के आदेश पर विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक खोज दर्ज की है कि श्रीमती अजहरुनिशा ने जमीर उद्दीन के साथ पुनर्विवाह किया था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने किस तारीख को पुनर्विवाह किया था। उन्होंने निचली अदालत को इस मुद्दे को तय करने और उस पर फैसला करने का निर्देश देते हुए मामले को रिमांड पर भेज दिया है। पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद मेरा विचार है कि रिमांड के बाद सी.ओ. द्वारा तैयार किया जाने वाला मुद्दा श्रीमती अजहरुननिशा के पुनर्विवाह से संबंधित मुद्दा है, न कि केवल पुनर्विवाह की तारीख से संबंधित मुद्दा है, इसलिए, यदि एसओसी की टिप्पणी केवल अपील पर निर्णय लेने के लिए है और इसका उद्देश्य सीओ के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में रिमांड आदेश प्रकृति में मध्यस्थ है और धारा 48 के तहत इसके खिलाफ संशोधन विचार योग्य नहीं था। इसलिए, समेकन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह स्वतंत्र मुद्दा तैयार करे कि क्या श्रीमती अजहरुनिशा ने जमीरुद्दीन के साथ पुनर्विवाह किया था, और पुनर्विवाह की तारीख भी, और पार्टियों के साक्ष्य लेने के बाद चकबंदी अधिकारी एसओसी के फैसले में टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेंगे।

28. अतः उपर्युक्त दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश ने केवल एक सारांश कार्यवाही के रिमांड के आदेश की पुष्टि की है, जो अपीलीय अदालत द्वारा तय की गई थी, जो भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ता के आदेश पर शुरू की गई थी, वे वार्ताकारी कार्यवाही हैं, जिन पर अभी तक गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त विवादों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका में गुण–दोष का अभाव है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे।

11.04.2022

अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विलंब क्षमादान आवेदन के साथ दिनांक 18042009 को 5 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं 500000 है। अपीलीय अदालत ने 16.12.2015 के फैसले के आधार पर प्रतिवादी की अपील पर विचार किया और 16.12.2015 के अपने फैसले के माध्यम से, विद्वान अपीलीय अदालत ने नायब तहसीलदार के दिनांक 17.02. 2009 के आदेश को रद्द कर दिया था और संबंधित पक्षों के साक्ष्य लेने और उनकी सुनवाई के बाद मामले को विशेष रूप से अपने गुण–दोष के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए नायब तहसीलदार की अदालत को वापस भेज दिया था। अपीलीय अदालत द्वारा रिमांड के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहां दिया गया हैः ''वीआरः एफआरएफआर डी एस वी ध केकेजे आई वी एच एच जी एस यूयकेवाईय 17–2–2009 को 17–2–नि.ा 2009 को यह पता लगाने के लिए क्लिक किया गया था, लेकिन 17–2009 को 17–2–2009 को 10,000,000,000,000,000,000,000,पू.ा 00,00,00,000,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00,00,00,00,00,00,00, 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,0000 के दशक के दौरान 17–2–2009 को 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 0000 के दशक के दौरान 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 अवोज यू.के.के.कीय की प=ावली वापस हो।''

दिनांक 23.02.2022 को वितरितः 11.04.2022 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल में 2022 की याचिका संख्या 319 (मेसर्स) बाल सुग्रीव सिंह और अन्य ...। याचिकाकर्ता वी प्रेम सिंह और एक अन्य ... प्रतिवादी अधिवक्ताः याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सिद्धार्थ सिंह।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे.

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि से निपटने से पहले और विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 के वकील द्वारा बढ़ाई गई दलीलों के प्रकाश में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाए गए सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए। क्षेत्र को नियंत्रित करने के रूप में सटीक कानून से निपटने की आवश्यकता है। दो समानांतर राजस्व कानून हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा मामले पर बहस करने के लिए अपने तर्क के समर्थन में लिए जा रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (इसके बाद इसे यूपीजेडए और एल.आर. अधिनियम के रूप में जाना जाता है) का प्रावधान है। वास्तव में उक्त अधिनियम द्वारा कवर किए गए पहलू से निपटने के लिए, यू.पी.जेड.ए. और एल एंड आर अधिनियम के प्रावधान, एक विशेष संविधि हैं, जिसे अधिनियम और अधिनियम के तहत परिभाषित कृषि भूमि पर प्रबंधन, विनियमों और अधिकारों के हस्तांतरण को शासित करने वाले राज्य द्वारा तैयार किया गया है, यही कारण है कि यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-बी के तहत तैयार संविधान की दसवीं अनुसूची में रखा गया है और इसे सीरियल नंबर 11 पर अपनी प्रविष्टि मिलती है।.

2 भारत के संविधान का अनुच्छेद 31-B कुछ अधिनियम और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 31-A के तहत निहित प्रावधानों के अपवाद के रूप में राज्य कानूनों द्वारा तैयार किए गए हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 31-B के तहत शामिल क़ानून से जुड़ा एक खंड है, जो एक वैध कानून है और कोई भी अधिनियम और विनियम जो दसवीं अनुसूची या इनमें से किसी में निहित नहीं हैं। इसके प्रावधानों को शून्य माना जाएगा या आधार पर शून्य हो जाएगा, कि ऐसे अधिनियम या विनियम कानून

के किसी भी अन्य प्रावधान के साथ असंगत हैं या अधिनियम के विधानमंडल के किसी भी प्रावधान द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को कम करते हैं।

3. जिसका अर्थ है कि जहां तक यूपी जेडए और एल.आर. अधिनियम का संबंध है, इसे अधिनियम की धारा 3 उपधारा (14) के तहत परिभाषित भूमि के अधिकारों को विनियमित करने या उससे निपटने के लिए एक विशेष अधिनियम होने का एक क़ानून दिया गया है, सिवाय उक्त अधिनियम के अध्याय VII की धारा 109 और 143 और 144 के तहत कवर की गई भूमि के अपवाद को छोड़कर। अधिनियम की धारा 229-बी के तहत घोषणा के अधिकार से संबंधित है; यू.पी. जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत होल्डिंग का विभाजन, अधिनियम की धारा 209 के तहत कब्जे के लिए एक मुकदमा और ऐसी अन्य प्रमुख सिद्धांत कार्यवाही, जो पार्टियों के अधिकार को निर्धारित करती है और कमोबेश यह पुरुष और महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार सहित संपत्ति के अधिकारों से निपटने वाली नियमित कार्यवाही का आकार लेती है।

4. यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही अधिनियम की धारा 341 के तहत निहित प्रावधानों द्वारा शासित होती है, जिसके आधार पर धारा 5 सहित कोर्ट फीस अधिनियम, परिसीमा अधिनियम के प्रावधान; साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम.5 के तहत प्रदान की गई कार्यवाहियों पर इसकी समग्रता में लागू किया गया है।

5. संविधि का दूसरा सेट जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता होगी, वह यह है कि राज्य विधायिका ने उत्तर प्रदेश नामक एक अधिनियम तैयार किया था। भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 (जिसे बाद में भू-राजस्व अधिनियम कहा जाता है), जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालय के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा लगातार देखा गया है

कि इसमें शासित कार्यवाही अध्याय III के उप-खंड-सी में निहित है; जो मुख्य रूप से मानचित्रों और राजस्व रिकॉर्ड की निरंतरता से संबंधित है, वे प्रकृति में सारांश हैं। उक्त अधिनियम, जिसके साथ हम अधिक चिंतित होंगे, के तहत कब्जा के हस्तांतरण के उत्तराधिकार की रिपोर्ट का प्रावधान है, जिसके आधार पर दावा किए गए अधिकार का विघटन होता है और अध्याय III के तहत विचार की गई प्रक्रियाओं के संबंध में प्रक्रियाओं को उन प्रक्रियाओं द्वारा विनियमित किया जाता है, जो उक्त अधिनियम के अध्याय X में निहित हैं। चूंकि अदालतें इस प्रकार बनाई गई हैं भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत या यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के तहत राजस्व न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, राजस्व न्यायालय मैनुअल को कार्यवाही को विनियमित करने की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए संकलित किया गया है, जो ऊपर उल्लिखित किसी भी अधिनियम के तहत विचार किया जाता है।

6. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य श्री अमर सिंह, श्री मान के पुत्र हैं। कहा जाता है कि राम प्रसाद का खाता नंबर 8-3 में 0.980 हेक्टेयर क्षेत्र में पड़ी जमीन के एक टुकड़े पर विशेष अधिकार है (इसके बाद इसे विवाद में संपत्ति कहा जाता है)। कहा जाता है कि श्री राम प्रसाद के पुत्र श्री अमर सिंह ने याचिकाकर्ता के पक्ष में 27.06.1997 को एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी और यह 27.06.1997 की उक्त पंजीकृत वसीयत की ताकत के तहत है, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि स्वर्गीय श्री अमर सिंह की संपत्ति पर अधिकार उन्हें हस्तांतरित किया गया था।

7. नतीजतन, याचिकाकर्ताओं ने भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत नायब तहसीलदार की अदालत में धारा 34 के तहत आवेदन दायर किया था, जिसे 2007-2008 के केस नंबर 30/106 के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उनका

नाम 27.06.1997 के वसीयतकर्ता के स्थान पर उनके नामों को प्रतिस्थापित करके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सके। इस प्रकार 2007-2008 के केस नंबर 30/106 के माध्यम से धारा 34 के तहत आयोजित कार्यवाही में, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उद्घोषणा जारी की गई थी, जिसमें धारा 34 के तहत आवेदन दायर करने से संबंधित बड़े पैमाने पर जनता को जानकारी दी गई थी, जिससे आपत्तियां आमंत्रित की गईं और याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी नंबर 1, वास्तव में 2007-2008 के 106 के केस नंबर 30 की कार्यवाही में दिखाई दिया है। लेकिन उसने परिश्रम के साथ कार्यवाही का विरोध करने में अपनी शिथिलता दिखाई थी और 20.01.2009 और 07.02.2009 को दो अवसरों पर प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्थगन की मांग की गई थी और जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार चुनौती नहीं दी गई थी और अंतिम रूप प्राप्त कर लिया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नायब तहसीलदार की अदालत ने 27.06.1997 की वसीयत के गवाहों की जांच करने के बाद, जिन्हें नायब तहसीलदार की अदालत के समक्ष पेश किया गया था और लेखपाल से रिपोर्ट बुलाकर विवादित भूमि पर कब्जे के तथ्य का पता लगाने के बाद, भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पर फैसला करने के लिए आगे बढ़ा था। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत विलंब क्षमादान आवेदन के साथ दिनांक 18042009 को 5 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं 500000 है। अपीलीय अदालत ने 16.12.2015 के फैसले के आधार पर प्रतिवादी की अपील पर विचार किया और 16.12.2015 के अपने फैसले के माध्यम से, विद्वान अपीलीय अदालत ने नायब तहसीलदार के दिनांक 17.02.2009 के आदेश को रद्द कर दिया था और संबंधित पक्षों के साक्ष्य लेने और उनकी सुनवाई के बाद मामले को विशेष रूप से अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए नायब तहसीलदार की अदालत को वापस भेज दिया था। अपीलीय अदालत द्वारा रिमांड के आदेश का प्रासंगिक हिस्सा यहां दिया गया है: ^^वीआर% एफआरएफआर डी एस वी / केकेजे आई वी एच एच जी एस यू;केवाई; 17-2-2009 को 17-2-fu.kZ 2009 को यह पता लगाने के लिए क्लिक

किया गया था, लेकिन 17-2009 को 17-2-2009 को 10,000,000,000,000,000,000,000,iw.kZ 00,00,00,000,000,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00,00,00, 00,00,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000,000,000,000,0000 के दशक के दौरान 17-2-2009 को 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,0000 के दशक के दौरान 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 अवोज यू.के.के.की; dh i=koyh okil gksAˆˆ

11. यह अपीलीय आदेश है, जिस पर याचिकाकर्ता ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 219 के तहत संशोधन को प्राथमिकता देकर सवाल उठाया है, और राजस्व बोर्ड के फैसले के पैरा 8 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, जो राजस्व बोर्ड के फैसले के पैरा 8 में किए गए थे, संशोधन को 19.01.2022 के फैसले और 16.02.2015 के रिमांड के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

12. पुनरीक्षण न्यायालय ने इसे बरकरार रखा था। इसलिए, रिट याचिका। याचिकाकर्ता के वकील ने 2015 के पुनरीक्षण संख्या 85 बाल सुग्रीव सिंह और अन्य बनाम प्रेम सिंह और अन्य के साथ-साथ 16.12.2015 के अपीलीय प्राधिकारी के फैसले को चुनौती देते हुए, वास्तव में, रिट याचिका के अपने संबोधन के दौरान, उस प्रश्न से मामले पर बहस की थी, जिसे रिट याचिका के पैरा 3 में तैयार किया गया है और संदर्भित किया गया है। जो यहाँ निकाले गए हैं:-

"3. वर्तमान में शामिल विवादास्पद प्रश्न इस प्रकार हैं: यह जानना कि क्या अपर कलेक्टर के पास उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील करने का कोई अधिकार क्षेत्र है और आदेश 41 नियम 23, 23 ए सीपीसीबी के अनुसार रिमांड की आवश्यकताओं के विरुद्ध विलंब क्षमादान आवेदन पर निर्णय लिए बिना, शीर्षक विवाद पर निर्णय लेने के लिए नामांतरण न्यायालय में मामला दर्ज करना। क्या आदेश 41 सीपीसी के प्रावधानों द्वारा शासित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपील पर निर्णय लेते समय अतिरिक्त कलेक्टर आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत आवेदन के बिना दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं?

13. वास्तव में, पहला तर्क जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने अपने तर्क के समर्थन में जोर दिया है, इस संदर्भ से है कि अपीलीय अदालत ने भूमि राजस्व अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार धारा 34 के तहत नए सिरे से आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को नायब तहसीलदार की अदालत में भेजकर कानून में गलती की है और अपीलीय अदालत को सारांश कार्यवाही होने के बाद से रिमांड की कोई शक्ति नहीं मिली है। अपीलीय अदालत द्वारा मामले को उसके नए निर्णय के लिए रिमांड पर देने की क्षमता के बारे में तर्क के पहले हिस्से का उत्तर उत्तर दिया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 216 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में दिया जा सकता है, जो यहां निकाला गया है: अपीलीय न्यायालय की शक्तियां। - 1) अपीलीय न्यायालय या तो अपील को स्वीकार कर सकता है या सरसरी तौर पर अस्वीकार कर सकता है। (2) यदि यह अपील को स्वीकार करता है, तो यह उसके खिलाफ अपील किए गए आदेश को उलट सकता है, बदल सकता है या पुष्टि कर सकता है; या इस तरह की आगे की जांच करने या इस तरह के अतिरिक्त सबूत ोंं को बीटाकेन के लिए निर्देशित कर सकता है जैसा कि यह आवश्यक सोच सकता है; या यह स्वयं इस तरह के अतिरिक्त सबूत ले सकता है; या वह

इस तरह के निर्देशों के साथ मामले को निपटान के लिए भेज सकता है जैसा कि वह उचित समझता है। जिसमें धारा 216 की उपधारा (2) में अनिवार्य की शक्ति विशेष रूप से अपीलीय प्राधिकरण के पास निहित की गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय प्राधिकारी के पास नीचे दी गई अदालत के समक्ष एक नए निर्णय के लिए रिमांड की अपनी शक्ति का अभाव था। याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क का दूसरा पहलू यह है कि प्रतिवादियों ने स्थगन के लिए उनके आवेदन को अस्वीकार करने के 20.01.2009 और 07.02.2009 के आदेशों पर सवाल नहीं उठाया था और 07.02.2009 को अपने गुण-दोष के आधार पर मामले पर फैसला करने के लिए आगे बढ़े थे, याचिकाकर्ता की धारा 34 के तहत एक आवेदन की अनुमति देते हुए, यह नहीं माना जा सकता है कि स्थगन के उपरोक्त उम्मीदवारों को चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार, न्यायालय द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर की गई कार्यवाही,

7 लंबित आवेदनों को शामिल करते हुए, उन कार्यवाहियों में, उन्हें अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना होगा। न्यायालय को मुकदमे के तहत व्यक्ति के अतीत के आचरण को नहीं देखना चाहिए, ताकि कार्यवाही की वैधता का आकलन किया जा सके, जिसे विचार के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह अनुपात 1997-98 (न्यायमूर्ति डीके सेठ) में रिपोर्ट किए गए फैसले में प्रदान किया गया है। इस न्यायालय का विचार है कि स्थगन आवेदन पर पारित आदेश, प्राधिकरण द्वारा पारित मुख्य आदेश को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे, जो 17.02.2009 को पारित किया गया है, जिसमें उत्परिवर्तन आवेदन की अनुमति दी गई है और देरी क्षमा आवेदन के साथ धारा 210 के तहत अपील दायर करके इसे चुनौती देने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। केवल इस बहाने कि

अपीलकर्ताओं को अपील की कार्यवाही का ज्ञान था, अपीलकर्ता ने स्वेच्छा से स्थगन आवेदन खारिज होने के बाद इसे चुनौती नहीं दी है और यह अपने आप में प्रधान प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित व्यक्ति के अधिकार को नहीं छीनेगा, अपील दायर करके इसे चुनौती देकर क्योंकि स्थगन की अस्वीकृति के वार्ताकारी आवेदनों को एक प्रक्रिया के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अपीलीय अधिकार से वंचित करने की कीमत पर। इसलिए, याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि चूंकि स्थगन के दो आदेशों को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए कोई अपील झूठ नहीं होगी, इस न्यायालय द्वारा भी स्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस मामले में तर्क दिया है कि नायब तहसीलदार द्वारा 17.02.2009 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था और अपील को 18.04.2009 को पसंद किया गया था, जैसा कि अधिनियम की धारा 214 के तहत प्रावधान किया गया है और इस तथ्य के बावजूद कि अपील के साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक आवेदन भी है। अपीलीय न्यायालय ने अपने गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने से पहले देरी को माफ नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं के वकील का यह तर्क कि अपीलीय न्यायालय ने विलंब क्षमादान आवेदन पर निर्णय लिए बिना गुण-दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का प्रयास किया है, एक बार फिर इस न्यायालय द्वारा तार्किक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विलंब क्षमादान आवेदन के विरोध में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए बचाव को बहुत विस्तार से निपटाया गया है।

2008-2009 की अपील संख्या 52/36 में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने अपने निर्णय के पैरा 2 में और विलंब माफी आवेदन के निहितार्थों पर विचार करते हुए, विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने आंतरिक पृष्ठ 3 में विलंब पर विचार किया है और आरडी 2011, खंड 112, 61 प्रेम नाथ सिंह बनाम राज्य में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, वास्तव में विलंब क्षमादान आवेदन पर विचार करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया है।

(क) सरकार ने विलंब क्षमादान आवेदन पर और इसके परिणामस्वरूप अपील के गुण-दोष के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज किया है और इसलिए एक टिप्पणी की गई है कि याचिकाकर्ताओं का तर्क, जिसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था, कि भूमि राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया को विशेष रूप से पैरा 197 और नियम 376 और 377 के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में, राजस्व न्यायालय मैनुअल के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अपीलीय न्यायालय ने इसके प्रभाव पर विचार किया था और उसमें यह देखने के बाद कि दयानंदी बनाम रुक्मा डी स्वर्ण और अन्य के मामलों में 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए; विशेष रूप से इसके संदर्भ में उल्लेख किया गया है, पैरा 13 में अपील को स्वीकार कर लिया गया था और मामले को रिमांड पर भेज दिया गया था। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलीय अदालत ने 16.12.2015 का निर्णय पारित करने से पहले अपने गुण-दोष के आधार पर देरी के प्रभाव पर विचार नहीं किया है क्योंकि अदालत का इरादा काफी स्पष्ट था, और जिस तरह से धारा 5 के निहितार्थ पर विचार किया गया है, यह माना जाएगा कि अदालत द्वारा और देरी के पहलू पर विचार करने में विचार किया गया था और इसलिए वकील द्वारा यह आधार लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि देरी को माफ नहीं किया गया था और देरी को माफ किए बिना मामले पर फैसला किया गया था, यह टिकाऊ नहीं है, क्योंकि दर्ज किए गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से अपीलीय अदालत के झुकाव को दर्शाते हैं कि उसने आवेदन की संभावना से अपना दिमाग लगाया और अपील पर फैसला करते समय देरी के पहलू पर विचार किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अपने पहले चरण के तर्क में तर्क दिया था कि सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 और आदेश 41 नियम 23-ए के तहत निहित प्रावधान, जो रिमांड की शक्ति के साथ निहित हैं, भूमि राजस्व अधिनियम 18 के तहत बनाई गई अदालतों पर लागू नहीं होंगे। इस न्यायालय ने बहस के दौरान, जब धारा 216 के तहत निहित

प्रावधानों का उल्लेख किया था और विशेष रूप से, जब प्रक्रिया स्वयं भूमि सुधार अधिनियम के अध्याय X द्वारा शासित होती है, तो इसके निहितार्थ क्या हैं?

सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 23 और आदेश 41 नियम 23-ए का धारा 210 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही को धारा 216 के साथ पुनः व्यवस्थित करने और मामले को उसके नए निर्णय के लिए भेजने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था कि 16.12.2015 का अपीलीय निर्णय एक स्पष्ट दोष से ग्रस्त है क्योंकि सीपी के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन, जो उत्तरदाताओं द्वारा उनकी अपील के समर्थन में रखा गया था, गुण-दोष के आधार पर तय नहीं किया गया था और इसके समर्थन में दायर दस्तावेज को सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन की अनुमति दिए बिना विचार किया गया था। 20. इस मोड़ पर ही न्यायालय ने एक बार फिर से याचिकाकर्ताओं से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता के अभाव में, कार्यवाही पर, जो प्रकृति में सारांशित हैं और भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं, सीपी के आदेश 41 नियम 27 के निहितार्थ कैसे दूर होंगे? अपने तर्क को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के मद्देनजर, इसके नियम 176 में निहित प्रावधानों ने सीपीसी के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता प्रदान की है, जो राजस्व न्यायालयों द्वारा आयोजित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए निकाले गए हैं। विशेष रूप से, उन्होंने सीपीसी के आदेश 41 के तहत निहित प्रावधानों का भी उल्लेख किया है जिसमें सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के तहत निहित प्रावधान शामिल हैं। राजस्व न्यायालय नियमावली के संगत नियम 176 को यहां दिया गया है: सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। आदेश XLI, आदेश XLII के नियम 2 से 4, 6 से 10, 15 से 29, 31 से 37 और डिक्री से अपील से संबंधित नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 99 और 144 के प्रावधान उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के तहत आदेशों से प्राप्त अपीलों पर लागू

होंगे। 22. याचिकाकर्ता के वकील की यह दलील कि राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के मद्देनजर, आदेश 41 के प्रावधान

सीपीसी का नियम 27 भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत सारांश कार्यवाही पर लागू होगा और विशेष रूप से, कार्यवाही की जांच करते समय, जो प्रकृति में सारांश है, इस न्यायालय का विचार है कि जब सारांश प्रक्रिया स्व-निहित संहिता के तहत आयोजित की जा रही है, जो इसके अध्याय 9 के तहत प्रदान किए गए अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को नियंत्रित करती है। इस घटना में, राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 176 के तहत प्रावधान किए गए राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के सामान्य नियम लागू नहीं होंगे, और इसके पीछे तर्क यह है कि यदि राजस्व न्यायालय मैनुअल के भाग-I को ध्यान में रखा जाता है, तो यह "राजस्व न्यायालयों में मुकदमा, अपील और अन्य कार्यवाही" से संबंधित एक सामान्य प्रक्रिया है। मामले में वर्तमान में शामिल सारांश कार्यवाही नहीं है, इसका अर्थ यह है कि सामान्य प्रक्रियात्मक नियम संविधि के तहत निहित विशिष्ट प्रक्रिया को ओवरराइड नहीं करेगा, जिसमें कार्यवाही आयोजित की जा रही है। इसलिए, राजस्व न्यायालय मैनुअल में वैधानिक बल नहीं होगा, क्योंकि कानून का कोई स्रोत नहीं है, जिसके तहत, इसे अधिनियम के तहत परिकल्पित सारांश कार्यवाही की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की यह दलील इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। पहली बार में अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया था, जो सभी राजस्व बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए थे। यह स्थापित कानून है, जिसके बारे में और विस्तार की आवश्यकता नहीं है, कि राजस्व बोर्ड के निर्णय, संवैधानिक न्यायालयों पर कानूनी और बाध्यकारी मिसाल नहीं हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के मामले के प्रयोजनों के लिए

उच्च न्यायालयों में उनका कोई प्रेरक मूल्य नहीं हो सकता है। सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 23 के तहत या सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 27 के तहत निहित प्रावधानों की प्रयोज्यता और याचिकाकर्ताओं द्वारा आधारित अनुपात को स्वीकार न करने का औचित्य इस आधार पर है कि यदि लगभग सभी निर्णयों पर विचार किया जाता है, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा आधारित प्राधिकारियों द्वारा निपटाया गया है, तो सभी कार्यवाही थीं। जो विशेष संविधि के अंतर्गत नियमित रूप से आयोजित किए गए थे और जिनके पास अधिनियम की धारा 34 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज करने के लिए भूमि राजस्व अधिनियम के तहत आयोजित सारांश कार्यवाही से निपटने के उद्देश्यों के लिए कोई संदर्भ नहीं है, जो केवल राजकोषीय प्रविष्टि है, जिसका लागू या विरोधी पक्ष के शीर्षक पर कोई प्रभाव या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है या होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ोें द्वारा दिए गए अधिकार उदाहरण के लिए हैं: - I। 1971 में रिपोर्ट किए गए फैसले में आरडी 490 अजीत सिंह बनाम। खम्भू सिंह और अन्य, यह एक ऐसा मामला था जो सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 के तहत अपीलीय अदालत की रिमांड की शक्तियों से निपट रहा था। और सी.पी.सी. के आदेश 41 नियम 25, लेकिन "यू.पी. जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 176 के तहत आयोजित कार्यवाही में, जो नियमित पक्ष पर थी," अर्थात एक होल्डिंग का विभाजन जो एक नियमित प्रक्रिया है, जिस पर सीपीसी के प्रावधान लागू होते हैं, यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 341 के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में। यह सिद्धांत तत्काल मामले में लागू नहीं होगा, जो भूमि राजस्व अधिनियम, 1901.II के प्रावधानों के तहत किया जा रहा था। दूसरा फैसला जिस पर याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वह यह है कि जैसा कि आरडी 1972 (2) राम लाल बनाम भागगू में बताया गया है, जो फिर से यूपी किरायेदारी (संशोधन) अधिनियम 1947 के पहलू और प्रावधानों और कार्यवाही को संचालित करने के निहितार्थ से निपट रहा था, जो उक्त प्रावधानों के तहत आयोजित किए गए थे। यह निर्णय भी राजस्व बोर्ड द्वारा दिया गया एक निर्णय था,

जिसका संवैधानिक न्यायालयों पर बाध्यकारी उदाहरण नहीं होगा और वह भी तब जब उक्त मामला, निर्णय के पैरा 4 में किए गए अवलोकनों के अनुसार, अधिनियम की धारा 209 के तहत आयोजित की जा रही कार्यवाही से संबंधित था, जिसे यूपी जेडए और एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के साथ पढ़ा जाना था। जो भी यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित कार्यवाही हैं और इसका सारांश कार्यवाही पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं और वह भी विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि ये कार्यवाही नागरिक प्रक्रिया संहिता द्वारा शासित थीं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने 1975 के आरडी 150 जमुना प्रसाद बनाम सत्य नारायण में रिपोर्ट किए गए एक और फैसले का हवाला दिया था, जिसके तहत आदेश 41 नियम 23 और 24 की प्रयोज्यता का मुद्दा उठाया गया था।

12 सी.पी.एस. को कार्यवाही के लिए इसकी प्रयोज्यता में माना जा रहा था, जो यूपी जेडए और एल.आर. अधिनियम की धारा 229-बी के तहत आयोजित किया गया था। इसलिए, उक्त निर्णय भी एक बार फिर से राजस्व बोर्ड का होने के कारण और अधिकारों की घोषणा के साथ विशिष्ट विषय के साथ काम करने के कारण, वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होगा। वह भी तब जब यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम के तहत कार्यवाही यू.पी.जेड.ए. और एल.आर.अधिनियम की धारा 341 द्वारा शासित होती है, जो सी.पी.सी. को लागू करती है। 1975 में आरडी नरेश बनाम एक और फैसले की सूचना दी गई। गांव सभा, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किया गया था, जहां लगभग एक समान सिद्धांत पर सीपी के आदेश 41 नियम 23 के आवेदन से संबंधित विचार किया जा रहा था, यानी अपीलीय न्यायालय द्वारा रिमांड की शक्तियों को रिमांड की अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करते हुए, वह भी एक ऐसा मामला था जिसे राजस्व बोर्ड द्वारा फिर से तय किया

गया था। अंत में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने 1969 आरडी 115 अल्गू बनाम सीताला प्रसाद में रिपोर्ट किए गए फैसले का संदर्भ दिया था, जो सीपीसी के आदेश 41 नियम 23 और 25 के प्रभाव से निपट रहा था, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किए गए रिमांड के लिए आधार। और क्या प्रारंभिक आधार पर मुकदमे का अंत और नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश देना बिल्कुल आवश्यक था! यह एक बार फिर एक ऐसा मामला था जिस पर राजस्व बोर्ड द्वारा कार्यवाही के संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा था, जहां वादी ने अधिनियम की धारा 209 के तहत मुकदमा दायर किया था, और भूमि का कब्जा हासिल करने का दावा कर रहा था, जिसे उन्होंने भूमिधर होने का दावा किया था। चूंकि यह निर्णय नियमित कार्यवाही से बाहर निकल रहा था और बोर्ड ऑफ रिवेंशन्यू द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए यह तत्काल मामले में लागू नहीं होगा जो विभिन्न अधिनियमों के तहत, सारांश मामलों से निपटता है। विशेष रूप से जब निर्णय देने वाली अदालतें अधीनस्थ अदालतें हैं, जिन पर उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

1324. याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया था कि यदि अपीलीय आदेश पर विचार किया जाता है, जब अपीलीय प्राधिकारी भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 210 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा था, तो उसे गुण-दोष के आधार पर मामले से नहीं निपटना चाहिए था, जैसे कि वह साक्ष्यों पर विचार करके और सराहना करके नियमित कार्यवाही का निर्णय ले रहा था। यह अपने गुण-दोष के आधार पर है, क्योंकि राजस्व न्यायालय मैनुअल के तहत, अध्याय 7 पैरा 176 के तहत निहित प्रावधानों के तहत, जिसका संदर्भ याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दिया गया है, एक सारांश कार्यवाही में है जो धारा 34 के तहत आयोजित की जा रही है, जो भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 210 के

तहत अपील की उत्पत्ति थी। यह एक नियमित मुकदमे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के इस तर्क की सराहना करने से डरता है कि तथ्यात्मक रूप से, यह पिटीशियन थे जो 27.06.1997 की पंजीकृत वसीयत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का दावा कर रहे थे, जैसा कि यह आरोप लगाया गया था, श्री अमर सिंह द्वारा निष्पादित किया गया था, और यह वही था जिसे 2007-2008 का केस नंबर 30/106 मिला था; भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत तहसीलदार की अदालत के समक्ष शुरू किया गया। यदि याचिकाकर्ता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जैसे कि यह नियमित मामले का परीक्षण है, तो उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है; क्योंकि वे अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक ही समय में गर्म और ठंडे होने की स्वतंत्रता नहीं ले सकते हैं; इसका कारण यह है कि यदि नायब तहसीलदार की अदालत द्वारा 17.02.2009 के सैद्धांतिक फैसले में दर्ज निष्कर्ष को ध्यान में रखा जाता है, तो वास्तव में यह याचिकाकर्ता ही थे जिन्होंने गवाह को प्रमाणित करके और हलका पटवारी की रिपोर्ट पर निर्भरता रखकर साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, ताकि कब्जे के तथ्य को स्थापित किया जा सके और इसके बजाय यह वह था जो कार्यवाही में कदम रख रहा था। मानो वह भू-राजस्व अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत चल रही कार्यवाही की आड़ में अपने मालिकाना हक का फैसला करवा रहे हों। यदि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं वसीयत को साबित करने के लिए मामले के गुण-दोष पर साक्ष्य का लाभ उठाया है, तो उस स्थिति में धारा 34 के तहत आदेश प्राप्त करने के लिए, अपीलीय न्यायालय, जो प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई अपील है, जो कार्यवाही की निरंतरता है, इसके निहितार्थ और उन विचारों पर विचार करने के लिए बाध्य था क्योंकि इसके बीज थे जो नायब तहसीलदार के आदेश से अंकुरित हुए थे। दिनांक 17.02.2009 को ही यह नहीं कहा जा सकता है कि

14 अपीलीय न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है क्योंकि अपीलीय न्यायालय उलट-पुलट का निर्णय देते समय तथ्यों और साक्ष्यों की सराहना करने के लिए बाध्य था। इस तर्क को एक अन्य दृष्टिकोण से और अधिक सराहा जा सकता है कि भूमि राजस्व अधिनियम के प्रावधान, निष्कर्षों के बावजूद, जो भूमि राजस्व अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी प्राधिकरण द्वारा दर्ज किए जाते हैं, धारा 219 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाही तक कार्यवाही के किसी भी चरण में, जो कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है, जो अभी भी सक्षम राजस्व न्यायालयों द्वारा नियमित अधिकारों की घोषणा पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा और यही कारण है, विधायिका ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 40-ए के तहत निहित प्रावधानों का प्रावधान क्यों किया था; भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही के तहत दर्ज किए गए निष्कर्षों के बावजूद, वसीयत के आधार पर दावा किए गए अधिकार की घोषणा पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां यूपी जेडए और एल.आर. अधिनियम की धारा 169 के तहत दोष की अनुमति है और यदि धारा 40-ए की भावना को ध्यान में रखा जाता है, यहां तक कि साक्ष्य की सराहना के निष्कर्ष भी किसी भी प्रतिबंध को पैदा नहीं करेंगे या कार्यवाही के लिए किसी भी पक्ष के हित के लिए हानिकारक होंगे, उनके नियमित अधिकारों का फैसला करने में। इस तर्क को जारी रखते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों ने पहले ही निषेधाज्ञा की डिक्री देने के लिए 2005 का सिविल मुकदमा संख्या 02 दायर किया था, जिसे 10.02.2012 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था और इसलिए वास्तव में प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्रतिबंध बनाया जाएगा। पूरी मानवता के साथ, निषेधाज्ञा की कार्यवाही, चाहे अभिलेखों में शीर्षक या स्वामित्व या कब्जे का पता लगाना प्रकृति में एकमात्र आकस्मिक हो और इसका कोई असर नहीं होगा और वह भी विशेष रूप से वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, जहां यहां तक कि सिविल मुकदमे का भी गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं किया गया था, इसे डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और इसलिए नागरिक

प्रक्रिया संहिता के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में, अभियोजन के अभाव में मुकदमे को खारिज करने पर, एक पहलू हो सकता है, जिसे कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा निपटाया जा सकता है, जो कार्यवाही के लिए किया जा सकता है या किया जा सकता है। जो भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 40-ए के तहत निहित प्रावधानों द्वारा बचाए जाते हैं। अंत में, यदि लागू आदेशों के निहितार्थ को ध्यान में रखा जाता है और विशेष रूप से

15. पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पैरा 8 में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आलोक में, रिमांड के अपीलीय न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने के लिए अपना तर्क निर्दिष्ट करने के लिए; वास्तव में रिमांड का आदेश एक मध्यस्थ आदेश का रूप लेता है, जहां कोई अधिकार अपनी योग्यता के आधार पर तय नहीं किए जाते हैं, बल्कि सभी मुद्दों को अभी भी सिद्धांत अदालत द्वारा पुनर्विचार के लिए खोला जाता है। जहां कार्यवाही को रिमांड पर भेज दिया गया है और इसलिए रिमांड का वार्ताकारी आदेश, चूंकि यह किसी भी अधिकार का अधिनिर्णयन नहीं है, एक वित्तीय अधिकार भी हो सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एआईआर 1981 सुप्रीम कोर्ट 707 क्षितिज चंद्र बोस बनाम कांची के आयुक्त में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में निर्धारित अनुपात को देखते हुए रिट याचिका पर रोक लगा दी जाएगी। निर्णय का पैरा 8 निम्नानुसार निकाला गया है: -8। तब उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि समय-समय पर किए गए कब्जे के छिटपुट कार्य प्रतिकूल कब्जे द्वारा स्वामित्व के अधिग्रहण के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों की प्रकृति के बारे में साक्ष्य का अध्ययन करने की भी परवाह नहीं की है और न ही यह पता लगाने के लिए कि क्या वे केवल छिटपुट या आकस्मिक थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह था कि प्रतिकूल कब्जा निरंतरता और प्रचार में प्रभावी और पर्याप्त होना चाहिए था। यहां, उच्च न्यायालय ने कानून के एक बिंदु पर गलती की है। कानून के लिए केवल यह आवश्यक है कि कब्जा खुला होना चाहिए और बिना किसी प्रयास के होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि कब्जा इतना प्रभावी होना चाहिए

ताकि इसे मालिक के विशिष्ट ज्ञान में लाया जा सके। इस तरह की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है जहां खिताब से बाहर होने की गुंजाइश है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हालांकि, निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वादी का कब्जा नगरपालिका के पूर्ण ज्ञान के लिए शत्रुतापूर्ण था। इस संबंध में हम निचली अदालत और अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त द्वारा शीर्षक और प्रतिकूल कब्जे के सवाल पर दर्ज किए गए सुविचारित निष्कर्षों से नीचे निकाल सकते हैं। ट्रायल कोर्ट (पुन: शीर्षक): "इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये रसीदें उपयुक्त भूमि से संबंधित हैं और इसलिए, वे वादी या उसके पिता द्वारा किराए का भुगतान दिखाती हैं। इस प्रकार, यह माना जाना चाहिए कि भूमि उन जमींदारों की थी जिनके भीतर यह जमींदारी थी। इसलिए, वादी के पिता ने उनसे समझौते द्वारा एक वैध शीर्षक प्राप्त किया। "इसलिए, मुझे लगता है कि वादी ने भी प्रतिकूल कब्जे से शीर्षक प्राप्त किया है क्योंकि वह और उसके पहले उसके पिता 1912 से 1957 तक इस भूमि के निरंतर कब्जे में थे, जब उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के तहत मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश से बेदखल कर दिया गया था। अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त (पुन: शीर्षक)

16 "इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि एक्सट्स। 5 से 5(जी) उन्हीं भूमियों से संबंधित हैं जिनके लिए हुकुमनामा (उदात्त 18) को मंजूरी दी गई थी क्योंकि वे उसी क्षेत्र के लिए हैं जैसा कि हुकुमनामा में दिया गया है और इनमें से पहला नाम, एक्स्ट 5 निपटान के बाद पहले वर्ष के लिए है और 20.5.1913 को दिनांकित है। निश्चित रूप से हुकुमनामा (उदा. 18) द्वारा, जो अप्रकाशित दस्तावेज है, मुकदमे में भूमि का निपटान किया जा सकता है और यह निपटान के पक्ष में अच्छा शीर्षक पैदा कर सकता है क्योंकि निपटान कृषि उद्देश्य के लिए था और कब्जे की डिलीवरी और किराया रसीदों के अनुदान के साथ था। पी डब्ल्यू 1, 2, 6, 9 और 8 (वादी) ने प्लाइंटिफ और उसके पिता के निरंतर कब्जे के बारे में कहा है। "इस प्रकार ऊपर बताए गए तथ्यों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्लाइंटिफ और उनके पिता 1912 से वर्ष

1954-55 तक मुकदमे में भूमि के कब्जे में आ रहे थे। नगरपालिका ने वादी और उसके पिता को 1924 से 1954-55 तक मुकदमा भूमि पर निर्माण सामग्री का भंडारण करने से रोकने के लिए कई प्रयास किए। इस प्रकार वादी के पिता 1928-29 के नगरपालिका सर्वेक्षण से पहले और बाद में मुकदमा भूमि के कब्जे में साबित हुए। मौखिक साक्ष्य पी डब्ल्यू 1, 6, 5, 8 और 9 भी साबित करते हैं कि 1912 में जमींदार द्वारा निपटान के बाद वादी और उसके पिता का मुकदमा भूमि पर वास्तविक कब्जा था। इसलिए, नगरपालिका सर्वेक्षण प्रविष्टि की शुद्धता की धारणा को वादी द्वारा इस मामले में सफलतापूर्वक खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी। [2001 (92) आर.डी. राम भजन और अन्य बनाम उप निदेशक, इलाहाबाद और एक अन्य। निर्णय के पैरा 4 और 6 को यहां दिया गया है: "4। एस.ओ.सी. के आदेश पर विचार करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने एक खोज दर्ज की है कि श्रीमती अजहरुनिशा ने जमीर उद्दीन के साथ पुनर्विवाह किया था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने किस तारीख को पुनर्विवाह किया था। उन्होंने निचली अदालत को इस मुद्दे को तय करने और उस पर फैसला करने का निर्देश देते हुए मामले को रिमांड पर भेज दिया है। पक्षकारों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद मेरा विचार है कि रिमांड के बाद सी.ओ. द्वारा तैयार किया जाने वाला मुद्दा श्रीमती अजहरुननिशा के पुनर्विवाह से संबंधित मुद्दा है, न कि केवल पुनर्विवाह की तारीख से संबंधित मुद्दा है, इसलिए, यदि एसओसी की टिप्पणी केवल अपील पर निर्णय लेने के लिए है और इसका उद्देश्य सीओ के लिए बाध्यकारी नहीं है। इस मामले के इस दृष्टिकोण में रिमांड आदेश प्रकृति में मध्यस्थ है और धारा 48 के तहत इसके खिलाफ संशोधन विचार योग्य नहीं था। इसलिए, समेकन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह स्वतंत्र मुद्दा तैयार करे कि क्या श्रीमती अजहरुनिशा ने जमीरुद्दीन के साथ पुनर्विवाह किया था, और पुनर्विवाह की तारीख भी, और पार्टियों के साक्ष्य लेने के बाद चकबंदी

अधिकारी एसओसी के फैसले में टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेंगे।

1728. इसलिए, ऊपर दिए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि पुनरीक्षण न्यायालय के आदेश ने केवल एक सारांश कार्यवाही के रिमांड के आदेश की पुष्टि की है, जो अपीलीय अदालत द्वारा तय की गई थी, जो भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ता के आदेश पर शुरू की गई थी, वे मध्यस्थ कार्यवाही हैं, जिन पर अभी तक गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए उपरोक्त विवादों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे-)
11.04.2022

आरती